

प्रेषक,

एल0एम0 पन्त,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त अधिशासी अधिकारी,
नगर पालिका परिषद, उत्तराखण्ड,
(संलग्न सूची के अनुसार)।

वित्त अनुभाग-1

देहरादून:दिनांक: 2। :जुलाई,2008

विषय:- द्वितीय राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष 2008-09 हेतु नगरपालिका परिषदों को धनराशि का संक्रमण (द्वितीय त्रैमासिक किश्त हेतु)।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि द्वितीय राज्य वित्त आयोग, उत्तराखण्ड की संस्तुतियों के आधार पर राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णयानुसार प्रदेश की 32 नगरपालिका परिषदों को संलग्न विवरण के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष 2008-09 की द्वितीय किश्त हेतु रु0 176884000.00 (रु0 सत्रह करोड़ अड़सठ लाख चौरासी हजार मात्र) की धनराशि संक्रमित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उपर्युक्त धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन संक्रमित की जा रही है:- (1) संक्रमित की जा रही धनराशि को कोषागार से आहरित करने के लिये बिल सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षरित किया जायेगा। संक्रमित की जा रही धनराशि का उपयोग शासनादेश सं0-1674/XXVII/(1)/2006 दिनांक 22 नवम्बर, 2006 द्वारा निर्गत मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अन्तर्गत किया जायेगा। इस धनराशि से किसी प्रकार का व्यावर्तन/समायोजन अनुमन्य नहीं होगा।

(2) नगर विकास विभाग संक्रमित धनराशि के नियमानुसार उपयोग की समीक्षा करेंगे तथा इसके समुचित उपयोग के लिये उत्तरदायी होंगे। कोषागार से आहरित धनराशि का बाउचर संख्या तथा दिनांक की सूचना महालेखाकार, उत्तराखण्ड एवं शासन के वित्त विभाग को भेजेंगे।

(3) निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय निकायों को आवंटित धनराशि के समय से उपयोग हेतु उत्तरदायी होंगे।

(4) शासनादेश में वित्त विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन विभागीय अधिकारी/वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तों में किसी प्रकार का विचलन हो तो वित्त नियंत्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित तुरन्त वित्त विभाग को दी जायेगी।

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2008-09 के आय-व्यय की अनुदान संख्या-07 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-3604-स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन -आयोजनेत्तर-01-नगरीय स्थानीय निकाय-192-नगरपालिका/नगर निकाय-03 राज्य वित्त आयोग द्वारा संस्तुत करें से समनुदेशन-00-20- सहायक अनुदान/ अंशदान/राज सहायता के नामें डाला जायेगा।

संलग्न:- यथोपरि।

भवदीय,
21/7/2008
(एल0एम0 पन्त)
अपर सचिव।

संख्या:- 517 (1)/XXVII(1)/2008 तददिनांक।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2- सचिव, नगर विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 3- मण्डलायुक्त, गढ़वाल/ कुमायूँ, उत्तराखण्ड।
- 4- निदेशक शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय, देहरादून।
- 5- समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 6- निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 7- समस्त वरिष्ठ मुख्य/ वरिष्ठ/ कोषाधिकारी उत्तराखण्ड।
- 8- विभागीय अधिकारी/ वित्त नियंत्रक/ मुख्य/ वरिष्ठ लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो।
- 9- निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड।
- 10- एन0 आई0सी0 सचिवालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।

आज्ञा से,
21/7/2008
(एल0एम0 पन्त)
अपर सचिव

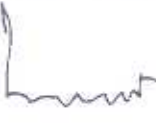
शासनादेश संख्या: 517 / XXVII (i) / 2008,

दिनांक: 21 जुलाई, 2008 का संलग्नक।

द्वितीय राज्य वित्त आयोग, उत्तराखण्ड द्वारा संस्तुत अनुदान के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2008-09 हेतु नगर पालिका परिषदों को द्वितीय त्रैमास के लिए संकर्मित धनराशि।

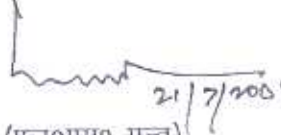
(धनराशि हजार रूपयें में)

क्र०सं०	शहरी स्थानीय निकाय का नाम	द्वितीय किश्त हेतु देय संकर्मण
1	2	3
1-	नगर पालिका परिषद	
1-	उत्तरकाशी	5653
2-	जोशीमठ	4283
3-	चमोली / गोपेश्वर	5553
4-	नई टिहरी	6418
5-	नरेन्द्र नगर	1323
6-	मसूरी	16553
7-	विकासनगर	1583
8-	ऋषिकेश	7415
9-	दुगड़डा	195
10-	कोटद्वार	4895
11-	श्रीनगर	2760
12-	पौड़ी	6657
13-	टनकपुर	2128
14-	रामनगर	3679
15-	नैनीताल	9158
16-	भवाली	361
17-	हल्द्वानी	15808
18-	जसपुर	3784
19-	काशीपुर	8333
20-	बाजपुर	2008
21-	गदरपुर	1902
22-	रूद्रपुर	13088

 21/7/2008

क्र०सं०	शहरी स्थानीय निकाय का नाम	द्वितीय किश्त हेतु देय संक्रमण
23-	किच्छा	3125
24-	सितारगंज	2454
25-	खटीमा	2520
26-	रुडकी	8486
27-	मंगलौर	3342
28-	हरिद्वार	15922
29-	पिथौरागढ़	7695
30-	अल्मोड़ा	4230
31-	बागेश्वर	2048
32-	रुद्रप्रयाग	3525
योग		176884

(रु० सत्रह करोड़ अड़सठ लाख चौरासी हजार मात्र)


 21/7/2008
 (एल०एम० पन्त)
 अपर सचिव, वित्त।